जनमत

मुद्दा

क्या आमजन को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकारों की प्राथमिकता में है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

इस सवाल पर आप संक्षिप्त प्रतिक्रिया भी भेज सकते हैं।

mudda@jagran.com

या

facebook.com/muddajagran

भूमि अधिग्रहण पर नहीं मिलेगा हाथ का साथ

- इस मुद्दे पर लड़ाई को लंबा खींचने की तैयारी में कांग्रेस
- आज सोनिया के नेतृत्व में विपक्ष का मार्च, मनमोहन भी होंगे शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस इस लड़ाई को लंबा खींचने को तैयार है। यानी इस मुद्दे पर सरकार को संसद में हाथ का साथ नहीं मिलेगा। सोमवार को सरकार के खिलाफ कामयाब प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस अब पार्टी अध्यक्ष की अगुआई में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेगा। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शिरकत करेंगे। इस मार्च में वाम दलों के साथ समूचा विपक्ष शामिल होगा। संसद के मौजूदा सत्र के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं।

शिवसेना भी झटका देगी : वही राजग घटक शिवसेना भी मोदी सरकार को जोर का झटका देने की तैयारी में है। सेना के सांसद इस मार्च से पहले या बाद में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं।

पुलिस कार्रवाई को बर्बर कहा : पार्टी ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई को बर्बर करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पुलिस ने पार्टी के शांतिपूर्ण मार्च पर जो बर्बर कार्रवाई की है पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। गौरतलब है कि इस संघर्ष में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। सोमवार रात को युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भेंट कर आंदोलन की जानकारी दी। गौरतलब है भूमि अधिग्रहण बिल पर संशोधन लोकसभा में पास हो चुके हैं। बिल में 9 नए संशोधनों को जगह दी गई है। वहीं राज्य सभा में सरकार के अल्पमत में होने के चलते सरकार को विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

> किसान और युवा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी का अभिमान तोड़ देगी। –अहमद पटेल
> सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव

बिल पास नहीं होने देगी कांग्रेस

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तय कर लिया कि मौजूदा सत्र में वह भूमि अधिग्रहण विधेयक को पास नही होने देगी। पार्टी की मंशा इस सत्र के बाद इसको लेकर जनता के बीच जाने की है। सत्र के दौरान आत्मचिंतन की छुट्टियों पर चल रहे राहुल की अगुआई में कांग्रेस इस मुद्दे पर लंबे आंदोलन की तैयारी में है। इससे पहले भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के विरोध में भट्टा परसौल से चलकर जंतर-मंतर व वहां से संसद घेरने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच तीखी नोक-झोक हुई।

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा जंतर- मंतर पर आयोजित किसान सत्याग्रह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजती पुलिस। जागरण

युवक कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ हिंसक

- पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के खिलाफ युवक कांग्रेस का प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जंतर-मंतर से संसद भवन घेरने की कोशिश करते समय पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके। इससे एक सिपाही की आंख में गंभीर चोट आई, उसे एम्स ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया है। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ीं। बाद में करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस भिड़ंत में 14 कार्यकर्ताओं और 10 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल किसी की तरफ से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से मंत्रणा की जा रही है।

कानून में संशोधन और मोदी सरकार के खिलाफ जंतर-मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई। हालांकि, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अनुपस्थिति कार्यकर्ताओं को अखर रही थी। धरना-प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, सचिन पायलट, अहमद पटेल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा व राजबब्बर समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जयराम रमेश ने कहा कि जब तक केंद्र द्वारा संप्रग सरकार के कानून को बरकरार नहीं रखा जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन पूरे देश में चलेगा और मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।

किसानों की बेदखली की साजिश : गोविंदाचार्य

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रमुख केएन गोविंदाचार्य ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2014 का प्रबल विरोध करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार विश्व बैंक के इशारे पर किसानों को खेती से बेदखल करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों की तरह प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।

सोमवार को राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के केंद्रीय कार्यालय पर गोविंदाचार्य पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि व चारागाह भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। कहा कि कृषि पर ज्यादा बजट की जरूरत है, लेकिन भारी कटौती कर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह अमेरिका परस्त नीतियों पर चल रही है। उसकी प्राथमिकताओं में जनविरोधी नीतियां साफ दिख रही हैं। उन्होंने मांग की कि वर्तमान बजट के अनुसार पंचायतों के लिए निर्धारित बीस लाख के बजट को बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जाए।

एक नजर

योग के जरिये नौकरशाहों को तनावमुक्त करेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार लगातार काम के बोझ तले दबे वरिष्ठ नौकरशाहों को योग और परंपरागत औषधियों के जरिये तनावमुक्त करने जा रही है। वह इसकी शुरुआत कार्मिक और कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों से कर रही है। उनके लिए 28 मार्च से दो दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यशाला लगाने का फैसला किया गया है। कार्यशाला में उप सचिव और निदेशक स्तर से लेकर ऊपर के अधिकारी शामिल होंगे।

पुल से लटकी बस, 10 की मौत

नई दुनिया, कोरबा : छत्तीसगढ़ में विश्रामपुर से कोरबा जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 यात्री घायल हो गए। 52 सीटों वाली इस बस में 75 यात्री सवार थे। सामने से आ रहे ट्रक से पहले पुल पार करने की आपाधापी में बस पुल की रेलिंग में जा टकराई। कई यात्री बस से नीचे 30 फुट गहरे नाले में जा गिरे। एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत आठ लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक की अस्पताल ले जाते समय तो दूसरे की उपचार के दौरान मौत हो गई। घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है।

समिति ने जताया खेद

नई दिल्ली, प्रेट्र : यूरोपीय संसद के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संघ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रशेल्स यात्रा के प्रस्ताव पर जवाब नहीं देने पर खेद जताया है। भारत की ओर से अगले माह वहां के दौरे के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इतालवी नौसैनिकों के मुद्दे को लेकर यूरोपीय संघ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कहा कि वह 28 सदस्यीय देशों के गुट को कहेगा कि वह भारत-यूरोप सम्मेलन के लिए जल्द तिथि तय करने की कोशिश करे। भारत के साथ यूरोपीय संघ के रिश्तों की समिति के अध्यक्ष जॉफरे वैन ऑर्डेन ने कहा कि मोदी के दौरे को लेकर तिथि पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन संघ की ओर से इसमें बहुत अधिक समय लग गया।

विपक्ष के गले नहीं उतरा आम बजट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राजग सरकार का पहला पूर्ण बजट विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। सोमवार को लोकसभा में जब आम बजट 2015-16 पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने जहां बजट के एक-एक प्रस्ताव को गरीब विरोधी और कारपोरेट हितों को बढ़ाने वाला करार दिया। वहीं भाजपा व राजग के अन्य दलों ने इन्हीं प्रावधानों को निवेश का माहौल बनाने वाला और गरीबों के हितों की रक्षा करने वाला ठहराया। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस यह भी कहती है कि बजट के जरिये राजग ने पूर्व संप्रग सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाया है।

आम बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कानून व पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि संप्रग की नीतियों को ही थोड़ा बहुत फेरबदल कर राजग उसकी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहा है। मसलन, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को ज्यादा फंड देने की वाहवाही सरकार लूट रही है, लेकिन इस आयोग की नींव पूर्व सरकार ने ही रखी थी। राजग सरकार भाग्यशाली है कि उसके कार्यकाल में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो चुकी हैं। हालांकि, वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को काबू में करने के लक्ष्य को एक वर्ष बढ़ाया है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने कहा कि यह बजट हाल के इतिहास में सबसे गरीब विरोधी और किसान विरोधी है। जबकि, इसमें कारपोरेट जगत के हितों को खूब बढ़ावा दिया है। बीजद के बी. माहताब ने विभिन्न मंत्रालयों के सालाना बजट में भारी कमी को चिंता की बात बताया। कई सांसदों ने जब 14वें वित्त आयोग के कारण राज्यों को कम आवंटन का मुद्दा उठाया तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अधिकांश राज्यों को आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद ज्यादा राशि मिलेगी। अगर राज्यों को 13वें वित्त आयोग के तहत राशि दी जाती तो केंद्र के पास काफी पैसा बचता। सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा सांसद हुकमदेव नारायण यादव ने बहस की शुरुआत कर कहा कि गरीबों के असली मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं क्योंकि पहली बार गरीबों की सुनने वाला बजट पेश किया है। अभी तक की सरकारें तो सिर्फ गरीबों के नाम पर आंसू बहाती थीं। लोजपा सांसद महबूब अली कैसर कहा कि यह बजट देश में निवेश का माहौल बनाएगा। इससे घरेलू व विदेशी कंपनियां निवेश के लिए आगे आएंगी। नई नौकरियां पैदा होंगी।

लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू

कांग्रेस के आरोप

1. बजट में कांग्रेस की नीतियों का ही अनुसरण
2. कारपोरेट जगत के हितों को देता है बढ़ावा
3. आम जनता को नहीं मिली कोई राहत
4. सामाजिक स्कीमों की धनराशि में कटौती

भाजपा का बचाव

1. गरीबों के हितों की होगी रक्षा
2. निवेश का माहौल बनेगा, विदेशी निवेश आएगा
3. सब्सिडी सही हाथों में पहुंचेगी
4. अर्थव्यवस्था की नीव होगी मजबूत

स्मृति से बोले शरद - कौन हैं आप

- महिलाओं पर जदयू प्रमुख के बयान पर राज्यसभा में हंगामा
- महिला सांसदों के आक्रामक तेवरों के बावजूद अपने रुख पर रहे कायम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : महिलाओं के रंग रूप पर अपनी टिप्पणियों को लेकर शरद यादव राज्यसभा में सोमवार को महिला सांसदों के निशाने पर रहे। हंगामे के बीच जदयू प्रमुख यादव अपने पूर्व के रुख पर कायम रहते हुए बहस की चुनौती दे डाली। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के तल्ख तेवरों पर झल्लाए यादव ने कहा 'कौन हैं आप? मंत्री रहकर के बैठिए और मेरी बात सुनिए।' हालांकि, यादव के इस रुख पर संसद की सभी महिला सांसद एकजुट हो गईं। उपसभापति ने भी बहस कराने की अनुमति नहीं दी।

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही शरद यादव के विवादित बयान पर महिला सांसदों ने एतराज करना प्रारंभ कर दिया। अपने बयान पर अड़े शरद यादव को जहां महिला सदस्यों की खरी खोटी सुननी पड़ी, वहीं उपसभापति ने उनकी बहस के आग्रह को नकार दिया। स्मृति ईरानी ने यादव के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाते हुए उन्हें शांत रहने और माफी मांगने को कहा।

ईरानी ने तल्ख लहजे में कहा कि महोदय (यादव) महिलाओं की चमड़ी का रंग देखकर कोई टिप्पणी न करें। इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। उपसभापति पीजे कुरियन के साथ अन्य सांसदों ने भी यादव की चुनौती और इस मसले पर बहस कराने की उनकी मांग का विरोध किया। कुरियन ने कहा कि वह गोरे व काले विषय पर बहस की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह शर्मनाक है। यादव ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि आखिर उन्होंने क्या कहा है? सांवली महिलाएं भारत में ज्यादा हैं। विश्व में भी उनकी संख्या अधिक है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यादव ने कहा कि इस संबंध में लोहिया के संघर्ष पर वह किसी से भी बहस को तैयार हैं। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जद यू नेता यादव के बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि उन्हें इस विवाद से न जोड़ा जाए। मैं इस बयान की निंदा करते हुए महिलाओं की आदर करते हैं। यादव से आग्रह करते है कि वह अपने बयान को वापस ले लें।

नई दिल्ली में सोमवार को बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बहस में उलझे शरद यादव व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। प्रेट्र

जागरण विचार

इसका कोई औचित्य नहीं कि विदेशी पूंजी पर चर्चा के दौरान दक्षिण भारतीय महिलाओं के सांवले शरीर और उनके नृत्य कौशल की चर्चा की जाए। इससे बेढब यह है कि इस पर आपत्ति के जवाब में महिला मंत्री तक को झिड़क दिया जाए और फिर यह कहा जाए कि इस पर बहस हो जाए कि दुनिया में सांवली महिलाएं ज्यादा हैं या गोरी? यह अपनी गलती छिपाने और मामले को दूसरा मोड़ देने का विचित्र उदाहरण है। ज्यादा गंभीर यह है कि ऐसा उदाहरण पेश करने वाले सांसद अपने रवैये पर अड़े हैं और कुछ अन्य सांसद उनका बचाव कर रहे हैं। क्या किसी को यह अहसास नहीं कि संसद की साख के लिए ऐसे प्रसंग ठीक नहीं?

मांझी बोले-बिहार में करोड़ों रुपये का एस्टीमेट घोटाला

- आरोप लगाया-ऊपर से नीचे तक जाता है कमीशन

जासं, मुजफ्फरपुर : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को अपनी पार्टी की रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा, जिस राज्य में गरीबों के हित की योजना को पैसे की कमी का हवाला देकर रद किया जाता है। वहां करोड़ों रुपये का एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। इसके संरक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं हैं।

मांझी ने ये बातें सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के पुलिस लाइन मैदान में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा (हम) की गरीब स्वाभिमान रैली के दौरान कही। मांझी ने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, भवन आदि की योजनाओं का एस्टीमेट कई गुणा बढ़ाकर बनाया जा रहा है। इसमें ऊपर से नीचे तक कमीशन जाता है। इसे रोकने के लिए अधिकारियों को लगाया गया तो भूचाल आ गया। कहा जाने लगा सबकुछ नाश हो जाएगा तब मांझी को हटाइएगा। परिणाम हुआ कि उन्हें पद से हटा दिया गया।

सपा विधायक पर बैंक मैनेजर को पीटने का आरोप

जासं, बदायूं : अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में अंदरखाने चल रहा विवाद सोमवार को सड़क पर आ गया। सपा विधायक और बैंक के चेयरमैन आशुतोष मौर्या ने महाप्रबंधक (जीएम) को न केवल अपने घर में बंधक बना लिया, बल्कि जमकर पीटा भी।

घटना तो रविवार की है, मगर उसका खुलासा सोमवार को हुआ। सपा के बिसौली विधायक आशुतोष मौर्या ने रविवार शाम करीब छह बजे अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के कार्यवाहक जीएम सचिन अग्रवाल को सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर बुलाया। चूंकि, विधायक बैंक के चेयरमैन हैं, इसलिए जीएम कुछ देर में कोठी पर पहुंच गए। बकौल जीएम, विधायक ने तत्काल बैंक से कुछ कागजात लाने को कहा। उन्होंने सोमवार को कागजात उपलब्ध कराने की बात की तो विधायक बुरी तरह बिफर गए।

अब स्वास्थ्य क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया'

- मधुमेह से कैंसर तक की जांच की स्वदेशी तकनीक उतारने की तैयारी
- बेहद सस्ते ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप का सपना अब होगा पूरा

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली

स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली बार स्वदेशी तकनीक पर आधारित कई आधुनिकतम और सस्ते उपकरणों को बाजार में उतारने की तैयारी हो गई है। इनमें सबसे खास मधुमेह और कैंसर जांच के उपकरण हैं। मधुमेह की जांच के लिए उपयोग होने वाली ग्लूकोमीटर स्ट्रिप तो मौजूदा कीमत के मुकाबले एक चौथाई कीमत में ही मिल सकेगी। जबकि, मैग्ना विजुअलाइजर की मदद से मुंह और गर्भाशय के कैंसर की शुरुआती स्तर की जांच छोटे से गांव में भी मुमकिन हो सकेगी।

आइसीएमआर की मेहनत : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की ओर से पिछले कुछ वर्षों के दौरान तैयार की गई विभिन्न तकनीक को बाजार में लाने के लिए सूथ हेल्थकेयर ने जोरदार तैयारी की है। आइसीएमआर के साथ हुए समझौते के तहत यह सात तरह की तकनीक को जल्दी ही बाजार तक पहुंचाएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक साहिल धारिया 'दैनिक जागरण' से बातचीत में बताते हैं कि उनका पहला ध्येय सस्ते ग्लूकोमीटर और इसके स्ट्रिप को लोगों तक पहुंचाना है।

ठंडा रखने वाले कपड़े : इस समझौते के तहत जिन तकनीक को बाजार में लाया जाना है, उनमें शरीर ठंडा रखने वाले कपड़े, विटामिन ए की कमी जांचने की किट, आयरन की जैव उपलब्धता के आकलन के लिए एलिजा फेरिटिन, हेपेटाइटिस-ई की जांच और लंग फ्लूक जांच के रीएजेंट शामिल हैं। आइसीएमआर का कहना है कि ये सभी तकनीक बिल्कुल नई हैं। कम लागत पर बड़े स्तर पर इनका उत्पादन भी हो सकता है। इनको बाजार तक लाने में भारतीय जैव तकनीक संस्थान (आइआइबीपीएल) तकनीकी सहयोग मुहैया कराएगा।

आ चुका डायरिया का टीका : कुछ दिनों पहले ही स्थानीय दवा कंपनी भारत बायोटेक ने भारत में ही विकसित रोटा वायरस के टीके बनाने शुरू कर दिए हैं। खुदरा बाजार में 1100 रुपये की कीमत पर बिकने वाले ये टीके अब सरकार को लगभग 60 रुपये में ही उपलब्ध होंगे।

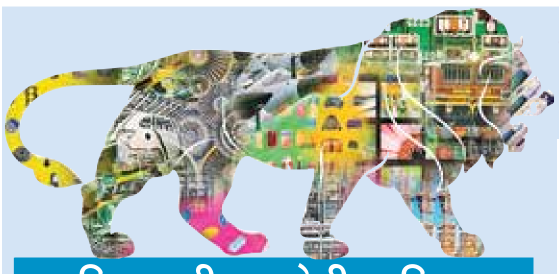

किफायती ग्लूकोमीटर स्ट्रिप

आइसीएमआर पहले ही सस्ते ग्लूकोमीटर और इसके स्ट्रिप तकनीक की जांच कर इसे मंजूर कर चुका है। अब इसके डिजाइन व मार्केटिंग की तैयारी के साथ इसका उत्पादन शुरू किया जाना है। सूथ हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक साहिल धारिया उम्मीद जताते हैं कि मौजूदा दो हजार से ढाई हजार रुपये के ग्लूकोमीटर की जगह ये एक हजार रुपये में उपलब्ध हो सकेंगे। इसी तरह ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप मौजूदा 20-25 रुपये की जगह पांच रुपये में मिलेगी।

गांवों में ही कैंसर जांच

एक साल के अंदर इन ग्लूकोमीटर के साथ ही कैंसर जांच के लिए मैग्ना विजुअलाइजर भी बाजार में उपलब्ध होंगे। आइसीएमआर के कैंसर शोध संस्थान 'इंस्टीट्यूट आफ साइटोलाजी एंड प्रिवेंटिव ओंकोलाजी' (आइसीपीओ) के वैज्ञानिकों ने मुंह और गर्भाशय के कैंसर का पता लगाने वाला मैग्ना विजुअलाइजर तैयार किया है। यह उपकरण महज दस हजार रुपये में उपलब्ध होगा। इससे पहले कैंसर की शुरुआती जांच के लिए कोल्पोस्कोप का सहारा लिया जाता रहा है, जो 50 हजार रुपये में मिलता है। जबकि नया उपकरण बिना बिजली के चलता है और कोई नर्स भी सिर्फ एक हफ्ते के प्रशिक्षण के बाद इसकी मदद से मरीजों की जांच कर सकती है।

तुगलकी फरमान : पश्चिम बंगाल में महिला खिलाड़ियों के बीच होना था फुटबाल मैच

छोटे कपड़ों की वजह से मैच रद

जेएनएन, कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में महिला खिलाड़ियों के बीच होने वाला फुटबाल मैच मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के चलते रद कर दिया गया। देश में फुटबाल को सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना की राजनीतिक दलों के साथ खिलाड़ियों ने भी कड़ी निंदा की है और कट्टरपंथियों के तुगलकी फरमान पर प्रशासन के रवैये की भी आलोचना की है। जबकि, तृणमूल कांग्रेस की स्थानीय विधायक ने इस प्रतिबंध को जायज बताया है।

पश्चिम बंगाल के प्रोग्रेसिव यूथ क्लब के गोल्डन जुबली समारोह के अवसर पर मैच का आयोजन किया जाना था। यह मैच मालदा जिले के चांदीपुर गांव में कोलकाता इलेवन व उत्तर बंगाल इलेवन के बीच होना था, जिसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी भी शामिल थीं। लेकिन, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने यह कहते हुए फुटबाल मैच पर प्रतिबंध लगाने की मांग की कि इस दौरान महिला खिलाड़ी बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं। क्लब के अध्यक्ष रेजा राजीर ने बताया कि आयोजन का लक्ष्य लड़कियों को आउटडोर खेल में प्रोत्साहन देना था। लेकिन, एक स्थानीय मस्जिद के इमाम मुफ्ती मकसूद ने धमकी देते हुए ऐसे आयोजन से बचने की बात कही, जबकि क्लब के ज्यादातर सदस्य भी मुस्लिम हैं। राजीर के अनुसार, इमाम ने फतवा जारी किया कि 'इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर मैदान में मैच खेलें।' तृणमूल कांग्रेस की स्थानीय विधायक व प्रदेश की मंत्री सावित्री मित्रा ने भी कट्टरपंथियों के प्रतिबंध का समर्थन किया है। हरिश्चंदपुर-एक के ब्लॉक विकास अधिकारी बिप्लव रॉय ने बताया कि इलाके में किसी भी तरह के जातीय तनाव से बचने के लिए जिलाधिकारी ने मैच रद करने का फैसला किया। फुटबाल खिलाड़ी नौसबा आलम ने कहा कि मुझे घटना पर विश्वास नहीं हो रहा, क्या यही 21वीं सदी का भारत है? कट्टरपंथियोंका अगला लक्ष्य सानिया मिर्जा होंगी, जिन्हें वे पूरे कपड़े में टेनिस कोर्ट पर उतरने को कहेंगे।

- जातीय तनाव से बचने के लिए प्रशासन ने लगाई आयोजन पर रोक
- तृणमूल कांग्रेस की स्थानीय विधायक व मंत्री ने किया समर्थन

> ये विश्वास के काबिल नहीं है कि बंगाल में कुछ धार्मिक कट्टरपंथी ऐसी मांग रखते हैं और प्रशासन उनके आगे झुक जाता है।'
> –मोहम्मद सलीम, माकपा नेता

बड़े नाम शामिल थे मैच में

इस फुटबाल मैच में राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नाम शामिल थे। जिसमें कृष्णा दास, सुजाता कर, अर्जुन अवार्डी शांति मल्लिक, फुटबाल की अंतरराष्ट्रीय संस्था फीफा की रेफरी अनामिका सेन, राष्ट्रीय हैंडबाल टीम की कप्तान अनीता रॉय प्रमुख हैं।

कृपाण के कारण स्टेडियम में घुसने से रोके गए सिख दर्शक

मेलबर्न, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के नियम के कारण न्यूजीलैंड में कुछ सिख भारत-जिंबाब्वे का मैच नहीं देख पाए थे। अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन ने इन सिख दर्शकों से सहानुभूति जताई है। न्यूजीलैंड सुप्रीम सिख काउंसिल आइसीसी केखिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है।

गौरतलब है कि क्रिकेट के महाकुंभ की आयोजक आइसीसी ने सात सिखों को कृपाण धारण करने के कारण स्टेडियम में घुसने नहीं दिया था। भारत और जिंबाब्वे के बीच यह मैच ईडेन पार्क में शनिवार को खेला गया था। प्रधानमंत्री जॉन की ने कहा कि उन्हें उन सिख दर्शकों से सहानुभूति है जिन्हें कृपाण धारण करने की वजह से मैदान में नहीं जाने दिया गया। जॉन की ने कहा, 'यह आइसीसी का टूर्नामेंट है, हमारा नहीं, इसलिए हम अपनी इच्छा उन पर नहीं थोप सकते।'

सामुदायिक रेडियो का होगा विस्तार

- शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, प्रक्रिया बनेगी सरल
- जेटली ने कहा, रेडियो तरंगे हैं सार्वजनिक संपत्ति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सूचनाओं के तेजी से प्रसार और उनमें जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार सामुदायिक रेडियो का विस्तार करेगी। सरकार ने इसके लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू करने और इसकी प्रक्रियाओं को सरल करने का वादा किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और यह सिर्फ एक मिथक है कि उन पर सरकार का एकाधिकार है, जिसे समाप्त किया जा रहा है।

जेटली ने पांचवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ किसी एक प्रसारक का अधिकार नहीं है, बल्कि श्रोताओं का भी इस पर अधिकार है। उनके पास सूचना का अधिकार है। सामुदायिक रेडियो के विचार को बढ़ावा देने की जरूरत है। जेटली ने कहा, दो दशक पहले ऐसा सोचा जाता था कि रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार है। अब यह मिथक टूट चुका है। रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं। जेटली ने इस मौके पर एक सार-संग्रह भी जारी किया, जिसमें सामुदायिक रेडियो से जुड़ी प्रेरक कहानियां शामिल हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव बिमल जुल्का ने बताया कि सरकार ने अब तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने से संबंधित 409 मंजूरियां दी हैं, जिनमें से 179 स्टेशन संचालित हो रहे हैं और अन्य कतार में हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 600 सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे।

नई दिल्ली में सोमवार को पांचवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़। जागरण